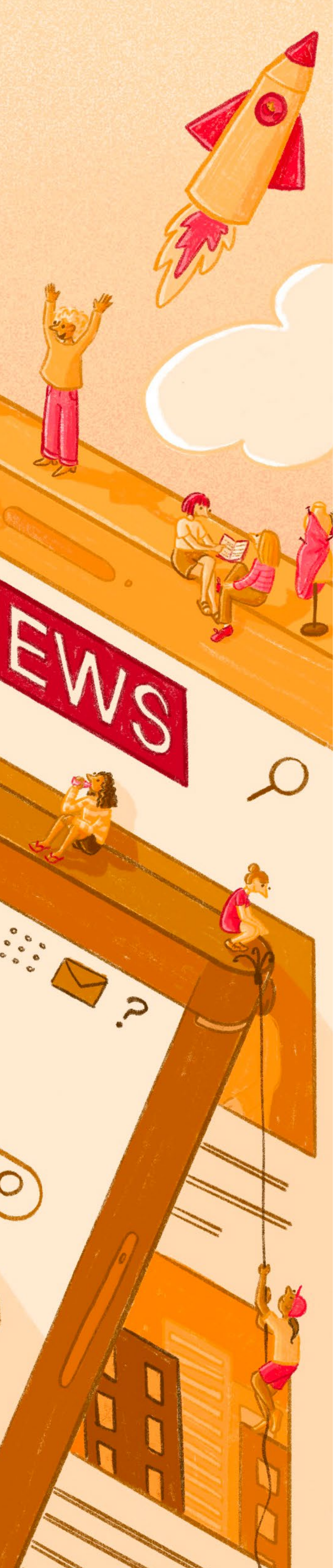

ALLIANCE FOR AFFORDABLE INTERNET

गैर-भागीदारी की लागतें

डिजिटल लैंगिक अंतराल के आर्थिक परिणाम

कार्यकारी सारांश

सरकारें डिजिटल लैंगिक अंतराल (gender gap) के कारण सैकड़ों बिलियन डॉलर की धनराशि गंवा रही हैं। इस अंतर को पाटने से अगले पाँच वर्षों में नीति निर्माता $524 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावना साकार कर सकते हैं।

विश्व भर में, लाखों लोग अभी भी इंटरनेट का उपयोग करने और ऑनलाइन भागीदारी करने में असमर्थ हैं — **और इसमें गैर-भागीदार महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है।** वैश्विक स्तर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के ऑनलाइन होने की संभावना 21% अधिक है जबकि अल्प विकसित देशों में यह संभावना बढ़कर 52% हो जाती है।

महंगे उपकरण और डेटा शुल्क, शिक्षा और डिजिटल कौशलों में असमानताएँ, महिलाओं और लड़कियों को ऑनलाइन होने से हतोत्साहित करने वाले सामाजिक मानदंडों और निजता, सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में भय सहित विभिन्न बाधाएँ महिलाओं और लड़कियों को इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त करने और ऑनलाइन भागीदारी से रोकती हैं।

डिजिटल गैर-भागीदारी कनेक्ट होने में असमर्थ महिलाओं और लड़कियों के अवसरों को तो सीमित करती ही है, इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हैं जिनसे सभी प्रभावित होते हैं। सैंकड़ों मिलियन महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण विश्व उन अकथनीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदानों से चूक रहा है जो कि इंटरनेट के लाभों का उपयोग करने में सक्षम होने पर वे कर सकती थीं।

इस रिपोर्ट में महिलाओं की डिजिटल गैर-भागीदारी के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। इसके अलावा, यह रिपोर्ट उस आर्थिक अवसर को रेखांकित करती है जो सरकारों के पास पूर्णतया समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं को शामिल करने के लिए उपलब्ध है।

डिजिटल गैर-भागीदारी की आर्थिक लागत को मापना

यह अनुसंधान निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (LLMICs) पर केंद्रित है जहाँ डिजिटल लैंगिक अंतराल अकसर सर्वाधिक होता है। डिजिटल गैर-भागीदारी के आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए यह रिपोर्ट सभी LLMICs के सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 70% से अधिक को शामिल करते हुए 32 LLMICs में लैंगिक अंतरालों का मॉडल तैयार करती है और इसे मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की पैठ बढ़ाने के आर्थिक प्रभाव की गणना करने वाले अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union (ITU)) के मौजूदा मॉडलों से जोड़ती है। यह मॉडल इन 32 देशों के सकल घरेलू उत्पादों (GDP) पर डिजिटल लैंगिक अंतराल के कुल प्रभाव का अनुमान देता है और अगर सरकारें इस समस्या का समाधान करने के लिए कार्य नहीं करती हैं तो भविष्य के प्रभाव की कल्पना करता है।

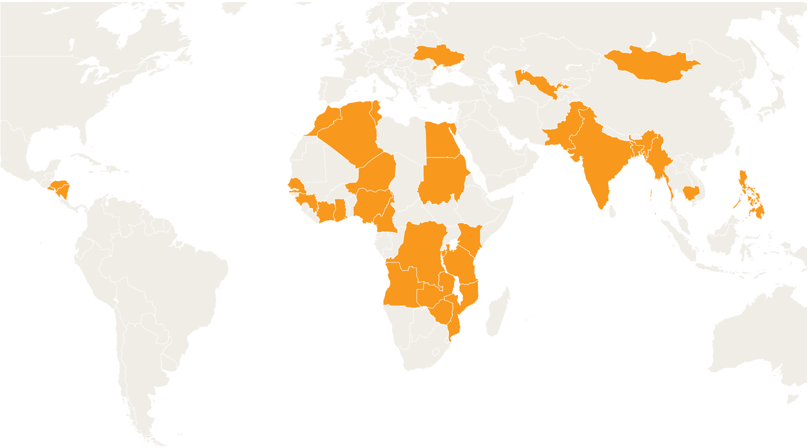

हमने क्या पाया

1

एक बड़ा डिजिटल लैंगिक अंतराल मौजूद है — और इसमें बेहतरी नहीं हो रही है। हमने जिन 32 देशों का अध्ययन किया, उनमें पुरुषों की आधी संख्या के मुकाबले एक-तिहाई से मात्र कुछ ही अधिक महिलाएँ इंटरनेट से कनेक्टेड थीं। 2011 के बाद से, लैंगिक अंतराल मात्र आधा प्रतिशत बिंदु घटकर 30.9% से 30.4% पर पहुँचा है।

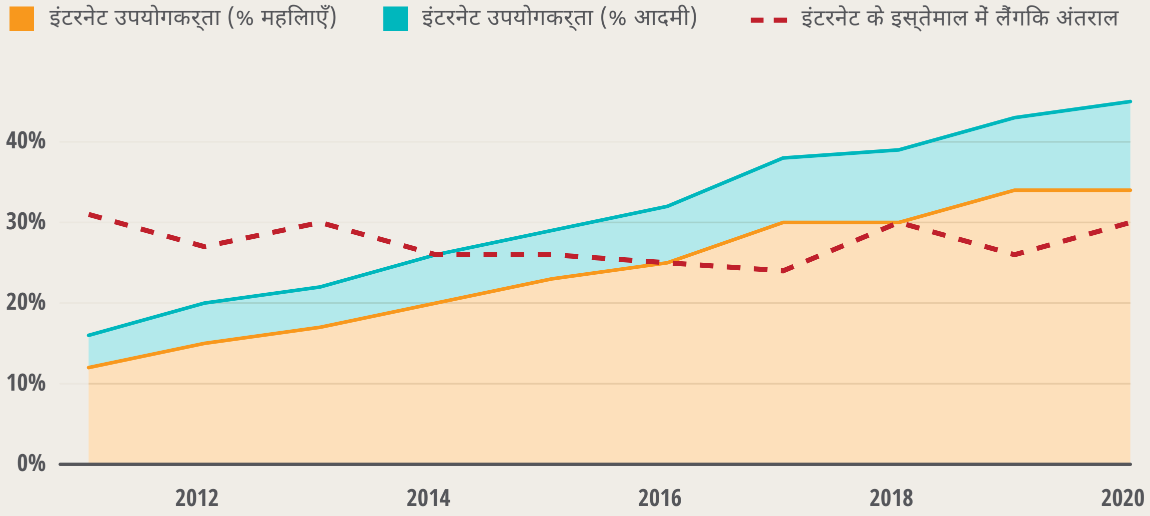

स्रोत: वहनीय इंटरनेट के लिए गठबंधन, 2021

2 **डिजिटल विश्व से महिलाओं की गैर-भागीदारी के परिणामस्वरूप विभिन्न देश GDP में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर गंवा चुके हैं।** 2020 में, GDP का नुकसान $126 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

3 **इस आर्थिक क्षति से अरब बिलियन डॉलर के करों के नुकसान से है जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में सुधार के लिए निवेश किया जा सकता था।** वर्तमान कर-से-GDP अनुपातों के आधार पर इन सरकारों द्वारा गंवाई गई उत्पादकता वार्षिक रूप से $24 अरब डॉलर के कर राजस्व में परिणत होती है।

4 **डिजिटल लैंगिक अंतराल को पाटने के लिए सरकारें जरूरी नीतियाँ नहीं अपना रही हैं।** एलायंस फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट (A4AI) द्वारा अपने वार्षिक मितव्ययिता प्रेरक सूचकांक (Affordability Drivers Index) में शामिल किए गए सभी नीतिगत क्षेत्रों में लिंग को सतत रूप से सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं। 2020 की मितव्ययिता रिपोर्ट में अध्ययन में शामिल 40% से अधिक देशों में महिलाओं के लिए इंटरनेट उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई सार्थक नीतियाँ या कार्यक्रम नहीं थे।

5 **नीति निर्माताओं के पास $500 बिलियन से अधिक का आर्थिक अवसर है।** इन देशों में डिजिटल लैंगिक अंतराल कम करने से 2025 तक आर्थिक गतिविधियों में अनुमानित $524 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी।

डिजिटल लैंगिक अंतराल को पाटना और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना

ये निष्कर्ष डिजिटल लैंगिक अंतराल की व्यापकता और कार्रवाई करने की इच्छुक सरकारों के लिए मौजूद अवसर को दर्शाते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्थाएँ कमज़ोर पड़ गई हैं, इसलिए सरकारें आर्थिक उत्पादकता और विकास के नए, सुदृढ़ स्रोत के रूप में डिजिटल विश्व की ओर देख रही हैं। यह विकास अवश्य समावेशी होना चाहिए और इसमें उन कार्यक्रमों, नीतियों और बुनियादी ढाँचे में निवेश अवश्य किया जाना चाहिए जो और अधिक महिलाओं को इंटरनेट के उपयोग में सक्षम बनाते हैं।

इस नीतिगत दृष्टिकोण में यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे में निवेश शामिल होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थिर, उच्च गति इंटरनेट पहुँच उपलब्ध हो और यह किफायती हो। लेकिन समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति को बुनियादी ढाँचे से आगे बढ़कर डिजिटल गैर-भागीदारी की आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक बाधाओं को भी अवश्य दूर करना चाहिए।

वेब फाउंडेशन द्वारा विकसित REACT ढाँचा पाँच मुख्य स्तंभों को परिभाषित करता है जो प्रौद्योगिकी में महिलाओं के समावेश को प्रोत्साहित करने संबंधी नीति विकसित करने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से नीति निर्माताओं को समग्र तरीका प्रदान करते हैं: **अधिकार, शिक्षा, उपलब्धता (पहुँच), सामग्री** और **लक्ष्य।** प्रभावी ब्रॉडबैंड रणनीति में ऐसी नीतियाँ अवश्य शामिल होनी चाहिए जो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की गारंटी देती हों; सभी के लिए कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करती हों; इंटरनेट पहुँच को उपलब्ध और मितव्ययी बनाती हों; प्रासंगिक, स्थानीय सामग्री को प्रोत्साहित करती हों; और नीति प्रक्रिया में जवाबदेही सृजित करने के लिए स्पष्ट नीतिगत लक्ष्यों को शामिल करती हों।

महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनी संपूर्ण क्षमता तक नहीं पहुँच सकती है। डिजिटल समावेशन मात्र अच्छी नीति ही नहीं — बल्कि अच्छी अर्थनीति भी है।